राहुल गांधी की 'न्यूनत आय योजना' हकीकत या चुनावी जुमला?

साल 2003 में लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील ने 'बोल्सा फैमिलिया' नाम की योजना चलाई थी. जिसके तहत सरकार गरीब परिवारों को भत्ता देती है. यूरोपीय देश फिनलैंड में भी साल 2017 के शुरुआत में कुछ इसी तरह की योजना की शुरू की गई थी, जिसके तहत बेरोजगार नागरिकों को एक न्यूनतम भत्ता दिया जाता है. हालांकि यह योजना ट्रायल बेस पर थी जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया है. इसके अलावा ईरान में भी नागरिकों को एक निश्चित आय भत्ता दिया जाता है ताकि बढ़ती मंहगाई से जनता को राहत दी जा सके.

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'कृषक सम्मान योजना' की जगह जो 'न्यूनत आय योजना' लाने की घोषणा की वह 6 हजार सालाना की जगह 12 हजार रुपये मासिक की लड़ाई है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हार के डर से इस योजना की घोषणा हुई। राहुल गांधी ने एक बड़ा ही चुनावी दांव चला जिसमें 20 फीसदी देश के गरीबों को 72 हजार रुपये सालाना देने का वादा कर डाला। इससे होने वाले लोकसभा चुनाव पर असर पडना लाजमी है क्योंकि यह लोक लुभावन वादे से जनता को अपनी-अपनी ओर खींचने के नए तरीकों का इस्तेमाल सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा या अन्य राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां सभी ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहीं है।

राहुल गांधी को अब जनता की गरीबी दिखाई दे रही है या लोकसभा चुनाव जीतने का नया हथकंडा क्योंकि कि केंद्र में एनडीए सरकार के पहले जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब भी तो गरीबी थी तब तो गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया। जो कि दो पंचवर्षीय यूपीए की सरकार केंद्र में थी तब कोई ऐसा ऐलान क्यों नहीं किया गया? क्या इसका कारण राजकोषीय घाटा था? जिसके चलते मनरेगा को छोड़ कोई भी किसानों या गरीबों के लिए योजना लाई गई हो। तब न ही पूरे देश के किसानों का कर्ज ही माफ किया गया, और आज किसानों की बात की जा रही है, अब कर्ज माफी को मुद्दा बनाया जा रहा है। यदि इतना ही गरीबों और किसानों से लगाव था तो इन योजनाओं को लाकर गरीबों की मदद पहले भी की जा सकती थी। अब जब दिनोंदिन लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो गरीबों और किसानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। यदि यूपीए की सरकार बनती है तो इस न्यूनत आय योजना को लागू करने में भी काफी मुश्किल होगी। क्योंकि गरीबी हटाने का वादा करना तो ठीक है लेकिन हर साल तीन लाख 60 हजार करोड़ रुपये सरकार कहा से जुटायेगी।

यह तो मानने की बात है। शिक्षा, चिकित्सा जैसे बजटों में भारी भरकम कटौती भी की जा सकती है। नहीं तो इस योजना को लागू करने में बहुत ही मुश्किल होगी। यह योजना सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन गरीब परिवारों के मुखिया समेत परिवार के सभी सदस्यों की आय देखी जायेगी तो बहुत ही कम लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। क्योंकि यदि परिवार में पाँच लोग हैं तो मुखिया समेत सभी की आय देखी जायेगी, पूरे परिवार की आय 12 हजार रुपये है तो इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर सभी की आय मिलाकर 12 हजार रुपये से जितनी कम होगी उतनी ही उन्हें दी जायेगी। तो यह ऊट के मुंह में जीरा जैसा साबित होगा।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'कृषक सम्मान योजना' की जगह जो 'न्यूनत आय योजना' लाने की घोषणा की वह 6 हजार सालाना की जगह 12 हजार रुपये मासिक की लड़ाई है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हार के डर से इस योजना की घोषणा हुई। अब देखना यह है कि भोली भाली जनता किधर जाती है यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा क्योंकि एक तरफ योजनाओं का लाभ उठा चुके लोग नरेन्द्र मोदी की तरफ रुख करते हैं या फिर कांग्रेस की घोषणा के चलते उधर रुख करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने युवा उद्यमियों को साधने का भी प्रयास किया है और उन्होंने कहा कि नया उद्यम लगाने के लिए तीन साल तक सरकार से किसी तरह की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।

बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार पर ठिकरा फोड़ते हुए बताया कि देश के 45 साल के इतिहास में सबसे अधिक बेरोजगारी आज मोदी सरकार के कार्यकाल में है। गरीबी मिटाने के लिए ऐसी योजनाओं से ज्यादा किसानों के फसलों का उचित मूल्य और उर्वरक, पानी एवं बीज, भंडारण जैसी सुविधाएं देने से ही उनकी समस्या सुलझ सकती है न कि ऐसी लोकलुभावन योजना के लाने से उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

अगर अर्थशास्त्रियों की माने तो न्याय सामाजिक सुरक्षा के लिए यह स्वागत योग्य प्रतिबद्धता है लेकिन इस प्रस्ताव की मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका वित्त पोषण कैसे होता है और किस प्रकार 20 प्रतिशत आबादी की पहचान की जाती है। इससे राजकोषीय बोझ पड़ेगा लेकिन कई अमीरों के पास गलत तरीके से अर्जित धन पड़ा है। यदि कोई भी ईमानदार नेतृत्व इस तरह के धन को बेहतर उपयोग के लिये लगा सकते हैं। इस योजना में काफी धन की जरूरत होगी और इसके क्रियान्वयन का भी मुद्दा बना रहेगा।

कुछ विशेषज्ञों ने यह भी माना कि भारत का कर -जीडीपी अनुपात दुनिया में सबसे कम है। हम अति धनाढ्यों पर उच्च दर से कर नहीं लगाते। हम धनी तथा मध्यमवर्ग को जो सब्सिडी दे रहे हैं वह गरीबों को दी जाने वाली सहायता के मुकाबले तीन गुना है। इसीलिए हमें अपनी सब्सिडी को सही जगह पहुंचाने के लिये उसे ठीक करना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाये तो यदि धनी वर्ग पर उच्च कर लगा दिया जाये तो सम्भव है। किन्तु मध्यमवर्ग की यदि सब्सिडी खत्म कर दी जाती है तो मध्यमवर्ग के बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो जायेगी। देश में मध्यमवर्ग तबका सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां मध्यमवर्ग को दी जा रही सब्सिडी में छेड़छाड़ नहीं करेंगी। इस योजना को लागू करने के लिये 2019-20 में 3.60 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 1.7 प्रतिशत की जरूरत होगी। अगले वित्त वर्ष के लिये जीडीपी 210 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। अब यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह इस योजना के लिए कहाँ से इतना पैसा लाते है वह तो अभी इस विषय कोई जानकारी ही नहीं दी। वित्तीय नजरिये से इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर चिंता जतायी जा रही है। कुलमिलाकर देखा जाये तो यह योजना सुनने में तो बहुत अच्छी है लेकिन इसको लागू करने के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या कुछ दिन इस योजना का पैसा देने के बाद इस योजना को बंद भी किया जा सकता है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले एक साल से प्रयास कर रहे हैं कि वे बीजेपी से अलग आर्थिक मॉडल जनता के सामने रखें. अलग आर्थिक नीतियों के सहारे ही वे जनता को कांग्रेस और बीजेपी में फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में किसान कर्जमाफी पर विशेष जोर दिया और हिंदी भाषी तीन राज्यों में सरकार बनते ही चुनावी वादों को पूरा भी किया. लोकसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए अब राहुल ने एक नया पैंतरा अपनाया है. उनका यह दाव भी कांग्रेस की नई आर्थिक नीति का हिस्सा मालूम पड़ता है. राहुल गांधी ने इस बार न्यूनतम आय गारंटी योजना का मुद्दा उठाया है. लेकिन क्या आने वाले चुनावों में राहुल गांधी और उनकी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा ?

भारतीय राजनीति को लेकर कभी-कभी कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई खास अंतर नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं. दोनों की आर्थिक नीतियां एक सी हैं, केवल मजहब को लेकर की जाने वाली राजनीति पर दोनों का स्टैंड अलग-अलग है. जहां बीजेपी वैचारिक रूप से दक्षिणपंथ की पक्षधर मानी जाती है, वहीं कांग्रेस अवसरवादी ढंग से समय के अनुसार उसका इस्तेमाल कर लेती है. लेकिन पिछले कुछ समय में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह परिपाटी बदलने की कोशिश की है. राहुल गांधी बीजेपी की आर्थिक नीतियों के जवाब में कांग्रेस की ओर से कुछ अलग किस्म की आर्थिक नीतियां पेश करने पर जोर दे रहे हैं. ताकि जनता को दोनों दलों के बीच के मुख्य अंतर को आसानी से समझाया जा सके.

विपक्षी दलों की तथाकथित एकता और अदृश्य महागठबंधन की दरकती दीवारों के बारे में भी राहुल को अंदाजा है. शायद इसीलिए कांग्रेस दूर खड़े होकर अदृश्य महागठबंधन का सपना देखने वालों को शाबासी तो दे रही है, लेकिन खुद वो उनके सपने में शामिल नहीं हो रही है. मोदी सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल को लगभग पूरा करने वाली है. इस दौरान राहुल गांधी ने लगातार मोदी सरकार की की छवि गरीब-विरोधी और पूंजीपति-समर्थक बनाने की हरसंभव कोशिश की है. मोदी सरकार आर्थिक क्षेत्र में किए गए कई वादों को पूरा नहीं कर पाई है. शायद इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस इस चुनाव में मोदी सरकार को लगातार आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस ने किसानों की कर्जमाफी को वादा कर तीनों राज्यों में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया. चुनाव जीतने के तत्काल बाद तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने सबसे पहले किसानों के कर्ज माफी का अपना चुनावी वादा पूरा भी किया. अब राहुल गांधी ने सभी गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी देने की बात कही है.

बता दें कि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने दो साल पहले ही इस तरह की योजना की चर्चा की थी. उन्होंने कहा था सभी तरह की सब्सिडी बंद करके, जीडीपी का मात्र साढ़े चार से पांच प्रतिशत खर्च करके ऐसी कल्याणकारी योजना शुरू की जा सकती है. माना जा रहा है कि छोटे किसानों सहित देश की कुल आबादी का लगभग चालीस फीसदी न्यूनतम आय गारंटी योजना के अन्तर्गत आ सकती है. यहां ध्यान देने वाली बात है कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत की बहुत हद तक वजह किसानों को राहत दने वाली योजनाए थी. ठीक दस साल बाद अब हालात 2009 लोकसभा चुनाव की ही तरह बन रहे हैं. एक फरवरी को मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही है. ऐसे में उम्मीद थी कि बजट में प्राथमिक आय योजना पेश की जाएगी. लेकिन अब न्यूनतम आय गारंटी की बात छेड़कर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बाउंसर का जवाब दे बाउंडरी से दिया है.

हालांकि न्यूनतम आय गारंटी योजना का कोई खाका अभी सामने नहीं आया है, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा है कि पार्टी इस योजना को घोषणा पत्र में पूरे ब्योरे के साथ शामिल करेगी. फिलहाल राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना की बात छेड़कर मोदी सरकार की मुश्किलें तो बढ़ा ही दी हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति के खेल में माहिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आने वाले बजट में राहुल के इस योजना का क्या तोड़ निकालते हैं. माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने अंतरिम बजट के पिटारे से जनता को राहत देने वाली कई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं. खैर, राजनीति की इस गहमागहमी के बीच इतना तो तय है कि गरीब जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं.

इन देशों में लागू हो चुकी हैं इस तरह की योजनाएं

राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में आयोजित एक सभा में न्यूनतम आय गारंटी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया की किसी भी सरकार ने ऐसी योजना नहीं लागू की है. लेकिन वर्तमान में कई देशों में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं तो कई जगह चल कर बंद हो चुकी हैं.

साल 2003 में लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील ने 'बोल्सा फैमिलिया' नाम की योजना चलाई थी. जिसके तहत सरकार गरीब परिवारों को भत्ता देती है. यूरोपीय देश फिनलैंड में भी साल 2017 के शुरुआत में कुछ इसी तरह की योजना की शुरू की गई थी, जिसके तहत बेरोजगार नागरिकों को एक न्यूनतम भत्ता दिया जाता है. हालांकि यह योजना ट्रायल बेस पर थी जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया है. इसके अलावा ईरान में भी नागरिकों को एक निश्चित आय भत्ता दिया जाता है ताकि बढ़ती मंहगाई से जनता को राहत दी जा सके.